भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 1371
उत्तर देने की तारीख-28/07/2025

आईआईएसईआर केंद्र

1371. श्री रामप्रीत मंडल:

क्या ***शिक्षा*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या सरकार की बिहार राज्य में भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर) केंद्र स्थापित करने की कोई योजना है;
(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ग) क्या बिहार के छात्रों को अन्य राज्यों में प्रवेश लेने में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है; और
(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकांत मजूमदार)

(क) से (घ): सरकार मौजूदा संस्थानों को सुदृढ़ करने और उनका विस्तार करने तथा उन्हें राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के साथ अनुकूलित करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसमें विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला और मानविकी में बहु-विषयक और समग्र शिक्षा की परिकल्पना की गई है। इस नीति में सभी क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता वाले अंतःविषयक शिक्षण और अनुसंधान को सक्षम बनाने के लिए बहुविषयक शैक्षणिक संस्थानों की ओर बढ़ने पर बल दिया गया है।

वर्तमान में, शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत देश में 7 भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर), 23 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), 25 भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी

संस्थान (आईआईआईटी), 32 राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी), 48 केंद्रीय विश्वविद्यालय (सीयू) और 21 भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) हैं। इनमें से प्रत्येक संस्थान में प्रवेश राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा के माध्यम से होता है, जो देश भर के विभिन्न शहरों में आयोजित की जाती है। इसलिए, बिहार सहित देश के किसी भी क्षेत्र के छात्र अपनी वरीयता, संबंधित परीक्षा में रैंकिंग और सीट की उपलब्धता के आधार पर इनमें से किसी भी संस्थान में प्रवेश ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त, एनआईटी पटना में डोमिसाइल कोटा है जिसमें 50% सीटें बिहार के छात्रों के लिए आरक्षित हैं।

वर्तमान में, बिहार में एक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी पटना), एक भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी भागलपुर), एक भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम बोधगया), एक राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी पटना) और दो केंद्रीय विश्वविद्यालय (बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय) हैं। उल्लेखनीय है कि बजट भाषण वर्ष 2025-26 में आईआईटी पटना में छात्रावास और अन्य अवसंरचना क्षमता के विस्तार के प्रस्ताव की भी घोषणा की गई थी। तदनुसार, छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए आवासीय सुविधाओं के विकास, शैक्षणिक ब्लॉक/ट्यूटोरियल भवन, कार्यशालाओं और अनुसंधान पार्क के निर्माण हेतु आईआईटी पटना को उच्चतर शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी (एचईएफए) ऋण के अंतर्गत सरकार द्वारा 644.54 करोड़ रुपये अनुमोदित किए गए हैं।

*****